

आचारसंहिता लागू होताच जाहिरात फलक उतरवले

**मीरा-भाईदर
महापालिकेची कारवाई**

मीरा रोड : मीरा भाईदर महापालिकेने शहरात वस स्टॉप व इतर ठिकाणी जाहिरात होईग लावण्यासाठी काही खासगी कंपन्यांना ठेका देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे महापालिकेने आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी सर्व जाहिरात होईंग महापालिकेने ताव्यात घेतल्या आहेत.

महापालिका जाहिरात विभागामार्फत शहरातील विविध भागात खासगी कंपनीला वीओटी तत्त्वावर होईंग, अँडपोल,



वॅकलिट ॲड वोर्ड या जाहिरात माध्यमांची उभारणी करून जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार देण्यात आले. सार्वत्रिक विधानसभा निवडणक आचारसंहिता मंगळवारापासून घाँपिल करण्यात आली आहे. आर्द्ध आचारसंहितेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी

करणे. वंधनकारकं आहे. त्यामुळे वीओटी तत्त्वावर देण्यात आलेल्या होईंगमधील ४८ ठिकाणी होईंग व मॅक्सेस मॉल ते गोल्डन नेस्ट सर्कल, ब्रॅण्ड फॉक्टरी ते डेल्टा गार्डन व सूटी कॉम्प्लेक्स ते मीरारोड स्टेशन येथील रस्ता दुपाजकांमध्ये अँडपोल, वॅकलिट ॲड वोर्ड

■ आचारसंहिता असेपर्यंत वसस्टॉप वडतर ठिकाणी जाहिराती करण्यासाठी परवानगी दिली असल्यास ती परवानगी आदेशाच्या दिनांकापासून ते आचारसंहिता कालावधीपर्यंत रद्द करण्यात येत आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त तथा परिवहन व्यवस्थापक अनिकेत मानोरकर यांनी सांगितले आहे.

६६. नंग उभारलेले आहेत. तसेच गालिका परिवहन विभागामार्फत वस यांव्यावर जाहिरात करण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. ते वस थांबे व उभारलेल्या सर्व होईंग, अँडपोल, वॅकलिट ॲडवोर्ड आचारसंहिता कालावधी संपेपर्यंत महापालिकेने ताव्यात घेतल्या आहेत.

ठोकमात पा. नं.२.

राज्यातील पोलिसांच्या रजा रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधानसभा निवडणकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्य पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या पोलिसांच्या सापाताहिक सुटीसह रजा बंद केल्या आहेत. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने मंगळवारी एक परिपत्रक जारी करत हे आदेश दिले आहेत. रजा बंदीमधून वैद्यकीय रजा आणि अत्यावश्यक कारणांसाठीच्या रजा वगळण्यात आल्या आहेत.

राज्य पोलिस दलातील विशेष पोलिस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र



विधानसभा निवडणूक २०२४ चे राज्य पोलिस समन्वय अधिकारी डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी संवैधित आदेश जारी केले. अनुचित घटना घटू नये म्हणून सतर्कतेचे आदेश पोलिस महासंचालक कार्यालयातून जारी करण्यात आले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेसाठी पोलिस बंदोबस्त

कायदा व सूच्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेसाठी पोलिस बंदोबस्त ठेऊनात करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, संवैधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक पार पडेपर्यंत पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक कारणाशिवाय किंवा वैद्यकीय रजा गणकू अन्य कोणत्याही कारणाशिवाय सुटी घेता येणार नाही.

मीरा-भायंदर में फेरीवालों से डराकर वसूली नए मनपा ठेकेदार पर लगाए जा रहे आरोप

■ फेरीवालों ने प्रभाग कार्यालय पर धरना दिया ■ मनपा प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी

अनिल चौधार | भायंदर

बाजार फीस वसूली ठेकेदार बदलते ही फेरीवालों पर आफत बरसनी शुरू हो गई है। नया ठेकेदार महाराष्ट्र सुरक्षा मंडल के जवानों का डर दिखाकर वसूली कर रहा है। इससे परेशन होकर काशीमीरा में फेरीवालों ने मीरा-भायंदर मनपा के प्रभाग कार्यालय पर धरना और नारेबाजी की। —

भायंदर के जिला महासचिव और पूर्व नगरसेवक अनिल भोसले ने बताया कि नया ठेकेदार फेरीवालों से 60 की बजाय 90 रुपए बाजार फीस वसूल रहा है, जबकि पड़ोस की टाँगे और सुंबई मनपा में 60 रुपए ही बाजार नीस है। ठेकेदार के आदमियों के साथ मीरा-भायंदर मनपा में तैनात महाराष्ट्र सुरक्षा मंडल के जवान और मानपा के अधिकारी भी रहते हैं। ज्यादा पैसा गांगने का विरोध करने पर वे फेरीवालों से डराते-धमकते हैं। उन्होंने बताया कि फेरीवालों ने ज्यादा पैसा देने से मना किया था, प्रशासन उनके ठेलों पर चुलडोजर चलवा दिया।



मनपा ने 32.73 करोड़ रुपए में दिया है ठेका

मीरा-भायंदर में बाजार फीस निजी ठेकेदार के माध्यम से वसूल की जाती रही है। मनपा प्रशासन ने तीन साल के लिए नया ठेका ओडीएस प्रोटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड को 32.73 करोड़ रुपए में दिया है, जबकि पहले यह रकम वार्षिक 7.48 करोड़ थी। देखा जाए तो तीन साल में 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके बदले में मनपा ने ठेकेदार को 60 की जगह 90 रुपए लेने की मजबूरी दी है।

फेरीवालों सहयोग नहीं कर रहे: पानपटे

मीरा-भायंदर महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर संभाजी पांडेंडे ने कहा कि बाजार फीस की रकम बढ़ाकर ठेका दिया गया है। ठेकेदार को फेरीवाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें अनुशासन में रखने के लिए महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडल के जवाब और मनपा अधिकारियों को ठेकेदार की मदद में लगाया गया है।

मनपा कर रही ठेकेदार की

मदद: मीरा रोड में धैर्या लगाने वाले सुभाष गुप्ता ने बताया कि 90 ही वहीं कई फेरीवालों से 120 रुपए बाजार फीस ठेकेदार के आदमी वसूल कर रहे हैं। इसी तरह पैण्डकर पाड़ा और भायंदर (पश्चिम) में रविवार साप्ताहिक बाजार में 200-200 रुपए वसूला जाता है। यह काम पहले ठेकेदार खुद करता था। अब मनपा अपने अधिकारी और महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडल के जवान देकर ठेकेदार की मदद कर रही है, जो फेरीवालों को डरा धमका रहे हैं। नियमों के मुताबिक यह पूरी तरह से गलत है।

मनपा को सिर्फ कमाई की

पड़ी है: सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत टिंह ने कहा कि मीरा-भायंदर मनपा को सिर्फ कमाई की पड़ी है। शहर की सड़कों और फुटपाथ चलना दुखार है। कब्जा जमाए फेरीवालों को हटाने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं है। शहर में 7-8 हजार अवैधत फेरीवाले हैं। चलने के लिए सुरक्षित और खुला फूटपाथ पाना नागरिकों का अधिकार है।

जल्द ही 41 बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर

गोपाल गुप्ता | चल्द

नालासोपारा में सरकारी जमीन पर बनाई गई 41 इमारतों में रहनेवाले करीब तीन हजार परिवार बेघर होने की कगार पर है। अगले सप्ताह में 300 पुलिस की नियारानी में वसई-विवार शहर महानगरपालिका ने तोड़क कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने वकायदा पुलिस प्रशासन से करीब 300 पुलिसकर्मियों की मांग की है। साथ ही विजली विभाग को विजली कन्काशन काटने का निर्देश दिया है। इससे शेष में रहनेवाले निवासी भयभीत हैं।

नालासोपारा के अग्रवाल नगरी स्थित डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लाट के लिए आरक्षित सरकारी जमीन वनी 41 अवैध इमारतों में रहने वाले लगभग तीन हजार परिवारों की मुसीबत बढ़ गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। यहां के निवासी घर बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अब फिर से मनपा ने उन्हें जल्द से जल्द घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। फिलहाल, किए ए पर रहने वाले लगभग घरों को खाली कर दूसरी जगह जाने लगे हैं, लेकिन जो लोग खुद के घर में रह रहे हैं, वे डरे हुए हैं। अगर वे घर खाली करते हैं, तो उनकी जिंदगीभर की कमाई से बनवा आशियाना आखों के सामने टूट जाएगा। मनपा का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर पुलिस की नियारानी में इमारतों की विजली-पानी आपूर्ति बंद कर तोड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सहायक आयुक्त ने पुलिस प्रशासन से करीब 300 पुलिस जवानों की मांग की है। उनकी पुलिस के आलाधिकारियों से बैठक भी हो चुकी है।

बता दें कि नालासोपारा (पूर्व) अग्रवाल, वसंत नगरी स्थित सर्वे क्रमांक- 22 से 34 और 83 तक की जगह एसटीपी प्लाट के आई

300 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में होगी कार्रवाई, अधिकारियों के साथ बैठक



पुलिस के आला अधिकारियों से मंगलवार और दुधवार को बैठक हुई है। मनपा की ओर करीब 300 पुलिसकर्मियों की मांग की गई है। अगले सप्ताह में तोड़क कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विजली विभाग को विजली खंडित करने का निर्देश दिया गया है। - मोहन संखे, सहायक आयुक्त, वसई-विवार मनपा



आरक्षित है। वर्ष 2006 से पहले नगरसेवक सीताराम गुप्ता और उनके बहुजन विकास आघाडी के पूर्व भतीजे अरुण गुप्ता ने फर्जी कागजात

बनाकर इस जमीन को बेच दिया था। वर्ष 2010-12 तक यहां चार-चार मंजिला 41 इमारतें खड़ी हो गईं। हालांकि हाई कोर्ट ने इस जमीन पर बनाई गई इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने नववर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मनपा से मार्गी है। यहां के निवासियों ने घर बचाने के लिए सड़कों पर उतारकर विरोध-प्रदर्शन किया था। सीएम एकनाथ शिंदे के पास भी गए थे, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला।

निजी संस्थाओं के साथ कार्यक्रम नहीं: MBMC

■ मीरा - भाईदर, (म). मीरा - भाईदर मनपा को विभिन्न संस्थाओं को पहुंच रही क्षति और कार्यक्रमों में मनपा को तब्बले नहीं दिए जाने के कारण अब उत्कृष्ट अधिक और निजी संस्थाओं के समय संयुक्त कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय अग्रुह व प्रशासक संजय श्रीपत्रकर काटकर ने निए हैं। वहाँ दें कि 21 नवंबर 2022 को मनपा के तब्बलोंन प्रशासक दिलोप दोले ने मनपा और निजी संस्थाओं की संयुक्त भागीदारी से विभिन्न कार्यक्रमों, कलाओं, सांस्कृतिक विरासत एवं सामाज कल्चर को प्रोत्सङ्खन देने और शहर की जनता को उसके बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से एक प्रशासकीय प्रस्ताव पारित किया था।



इसके अनुरूप कई कार्यक्रम आयोजित हित्ते गये, लेहिन ऐस देखा गया कि निजी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित हित्ते जाने वाले कार्यक्रमों में जनशुद्धकर मनपा की भागीदारी को कम तरज्जु देकर आयोजक अपनी संत्या तथा उनके प्रमुख व्यक्तियों का प्रवारप्रसार अधिक कर रहे थे। परित प्रस्ताव के अनुसार इन कार्यक्रमों के आयोजन से शहर के अधिक से अधिक नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर कार्यक्रमों की जानकारी एवं ताम आम जनता तक पहुंचाया जाना था। इसके लिए मनपा का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल करना था। यहाँ निजी संस्थाओं के भागीदारी से किए

महानगरपालिका के राजस्व व संपत्तियों की हो रही थी क्षति



जाने वाले पिगिन कार्यक्रमों के लिए मनपा अपने हाल, मैदान आदि संपत्ति उन्होंनि: शत्क सुहृद्या कराती थी। उन कार्यक्रमों से मनपा को आशानीत कोई ताप नहीं हो रही थी तो वही दूसरी तरफ निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से मनपा के हाल, मैदान आदि की दुर्दशा और क्षति भी हो रही थी। इसे देखते हुए मनपा अग्रुह व प्रशासक काटकर ने अब निजी संस्थाओं की सहायता से मनपा द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के प्रशासकीय प्रस्ताव को अनुरूपी दी।

नायगांव के कोलीवाड़ा श्मशान भूमि की स्थिति बदलतर मोबाइल फोन की रोशनी में किया गया अंतिम संस्कार

■ चसई, (स). नायगांव पश्चिम के कोलीवाड़ा इलाके में अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया गया श्मशान घट जर्जर हो चुका है। खासकर विजली की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को रात के अंधेरे में मोबाइल टॉच की रोशनी में अंतिम संस्कार करने की जीवत आ गयी। नायगांव पश्चिम स्थित कोलीवाड़ा क्षेत्र में दाह संस्कार के लिए एक श्मशान घट तैयार किया गया है, लेकिन रखरखाव की अनदेखी के कारण यह श्मशानभूमि बेहद जर्जर अवस्था में है। पिछले एक से डेढ़ माह से जलाने वाली जगह पर पत्रे फटे हुए हैं। इससे बारिश का पानी सीधे सतह पर पिता है और शवदाह में भारी परेशानी पैदा करता है। लकड़ी भी जाती है, जिससे वह जल्दी आग नहीं पकड़ती। लोहे के खंभों में जंग लग गया है। लगाई गई जलियां भी नष्ट हो गई हैं। जंग लगे पोल कभी भी गिरकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यहाँ विजली की सुविधा नहीं है, इसलिए रात में शव का अंतिम संस्कार करना बेहद मुश्किल होता है।



मनपा ने की इस क्षेत्र के साथ घोर उपेक्षा

■ यहाँ के नागरिकों का कहना है कि, हाल ही में नायगांव कोलीवाड़ा से एक शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घट लाया गया था। दिजली की सुविधा न होने के कारण श्मशान में बहुत अंधेरा पसरा था।

■ ऐसे में उह मोबाइल फोन की रोशनी में, स्कूटर की डेलाइट के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा। नागरिकों का आरोप है कि मनपा ने इस क्षेत्र के श्मशान की उपेक्षा की है।

■ नागरिकों ने श्मशान में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि यहाँ के नागरिकों के सामने दोवारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो।

www.mumbai.nbt.in

| नवभारत टाइम्स | मंगलवार | मुंबई | १७ अक्टूबर 2024

मुंबई

भीरा रोड | भाईदर | नायगांव | वरसई | नालासोपारा | विरार | बोइसर | पालघर | दहाणू | नवी मुंबई | पनवेल | रायगढ | उरण | ढाणे | कलवा |

नालासोपारा में घर खाली कराने के लिए मनपा ने मांगा पुलिस बंदोबस्त

■ सुरेंद्र नेगी, नालासोपारा: नालासोपारा: नालासोपारा की विवादित 41 अवैध इमारतों पर अब तोड़क कार्रवाई होना लगभग तय हो गया है। वहीं, यहां रह रहे तीन हजार परिवार वालों को कहीं से भी राहत नहीं मिली है। इधर, मनपा ने पुलिस विभाग को पत्र देकर पुलिस बंदोबस्त की मांग की है।

इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग ने मनपा से थोड़ा समय मांगा है, क्योंकि पर्याप्त पुलिस यत्न उपलब्ध नहीं होने की वजह से तोड़क कार्रवाई रुकी हुई है। मनपा के संवैधित अधिकारी ने कहा है कि पुलिस को दो बार पत्र दिया जा चुका है। दो दिन में आगे बंदोबस्त नहीं मिला, तो हम अपनी टीम के साथ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह घरों से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने घरों को टूटना नहीं देखना चाहते हैं। नालासोपारा पूर्व अग्रवाल नगरी के लक्ष्मी नगर डॉगिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लॉट की आसपास जमीन पर बसा है। इस जमीन पर लगभग 41 इमारतें खड़ी हैं, जिनमें लगभग तीन हजार परिवार रहते हैं। ये लोग लगभग 15 सालों से यहां रह रहे हैं। इहें किसी भी वात का पता नहीं था कि

41 अवैध इमारतों पर तोड़क कार्रवाई को लेकर गरमाया माहोल

3,000 परिवारों को राहत नहीं

निवासियों ने कहा, घाह कुछ भी हो जाए, घर से बाहर नहीं निकलेंगे

मॉनसून के दौरान दी गई थी राहत



वह जिन इमारतों में घर रहते हैं, वह अवैध है। कुछ महीने पहले जब एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और उसके बाद कोर्ट ने सभी इमारतों को अपने घरों को बचाने के लिए यहां के निवासियों ने सड़कों पर उत्तरकर कई वार अवैध करार देते हुए मनपा को तोड़ने का आदेश जारी किया, तब यहां के लोगों की

नीद उड़ गई।

कई बार किया गया विरोध प्रदर्शन: अपने घरों को बचाने के लिए यहां के निवासियों ने सड़कों पर उत्तरकर कई वार विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और मनपा मुख्यमंत्री पर

घरना-प्रदर्शन भी किया गया है। लोगों ने सुश्रीम कोर्ट तक का दूर्याजा छठखटाया है, लेकिन राहत नहीं मिली। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बोट बैंक के लिए उन्हें घर बचाने के आश्वासन दिए लेकिन उनकी यात्रा का कोई असर नहीं हुआ।

WhatsApp DP reveals house help's theft

Poonam Apraj
MUMBAI

A house help's theft at a businessman's residence in Kandivali came to light after the stolen items were spotted in the woman's WhatsApp status. Mandar Narkar, 35, had employed two women - Yashoda Thapa for cooking and Rupali Singh for cleaning. Singh, who had been responsible for maintaining the 3-bedroom apartment, informed Narkar's family on October 7 that she was resigning due to personal family issues. On Dussehra, Narkar's wife noticed a missing saree and contacted Singh, who claimed she had placed it in the wardrobe. Later, Narkar came to know that Singh had taken a bag from the house on October 7 around 9am. Suspicion grew when, on October 12, Narkar's wife saw Singh's WhatsApp status, in which she was wearing her wristwatch and dress. Later, it was found that she had stolen other items too, including jewellery.

Vijay Com

22 MBMC personnel trapped for taking bribes over 19 years

Suresh Golani
MIRA BHAYANDAR ✓

Twenty-two personnel, including 10 officials, from various departments of the Mira Bhayandar Municipal Corporation (MBMC) have landed into traps laid by the Anti-Corruption Bureau (ACB) for accepting bribes in the past 19 years. A couple of elected representatives also have been charged for graft.

The information was sourced out under the Right to Information (RTI) Act by social activist Krishna Gupta. Ironically, the reply to the RTI query has been given by an assistant commissioner who himself had landed into the custody of the ACB on alleged charges of accepting a bribe amounting Rs1.75 lakh from a hotelier in 2013.

As per the reply, while one official has been recently acquitted in a 14-year-old bribery case, investigations are still underway in the remaining cases with no con-

545 traps

A cursory glance at the statistical records uploaded on ACB's official website reveals 545 traps registered across the state between January 1 and October 14 this year, as compared to 661 in the corresponding period last year, which indicates an 18% drop.

victions. Notably, most of the tainted personnel have not only rejoined regular services after brief suspensions, they have also managed to bag plump postings. Gupta has alleged that in addition to the 22 cases in which personnel have been caught red-handed, the ACB had sought permission to probe nearly 27 complaints related to corruption and misappropriation of funds, including an ambulance scam, in the past five years. "However, permissions were denied in all cases," alleged Gupta.

International e-wa